सं. ए-45011/4/2023-समन्वय.II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को जनवरी, 2023 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 2309 5091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. वित्त राज्य मंत्री के प्रधान सचिव, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (आ.का.) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।
11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, एएस एंड एफए (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशा./समन्वय/सीएण्डसी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, एएस (जी 20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय -2)/ओएमआई / क्रिप्टो आस्ति और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी)/ संयुक्त सचिव (आईएनवी)/संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (एफएम)/सभी सलाहकार/सीएएए
17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल - 2022

सं. ए-45011/4/2023-समन्वयII
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

विषयः जनवरी, 2023 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश

I. इस माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

वृहतआर्थिक अवलोकनः

मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के कारण, आईएमएफ ने, विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के जनवरी 2023 के अपडेट में वैश्विक उत्पादन 2021 के 6.2 प्रतिशत से घटकर 2022 में 3.4 प्रतिशत और 2023 में 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने, वैश्विक आर्थिक संभावनाओं (जीईपी) के जनवरी 2023 के संस्करण में वैश्विक वृद्धि दर 2022 के 2.9 प्रतिशत से घटकर 2023 में 1.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 के 8.8 प्रतिशत से घटकर 2023 में 6.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जबकि महामारी से पहले (2017-19) के लगभग 3.5 प्रतिशत के स्तर से ऊपर रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही, विश्व बैंक ने वैश्विक शीर्षक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति वर्ष 2023 में 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जो वर्ष 2015-19 के औसत 2.3 प्रतिशत से अधिक है।

वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार की स्थिति खराब होने की उम्मीद है क्योंकि मौद्रिक सख्ती से दोहरा प्रभाव पड़ेगा - यह मांग को कम करेगा और परिणामस्वरूप, व्यापार की मात्रा; और, एक ही समय में, कम कीमतें और, तदनुसार, व्यापार का मूल्य कम करेगा। विश्व बैंक के अनुसार, वैश्विक व्यापार वृद्धि वर्ष 2022 में 4.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 1.6 प्रतिशत होने की उम्मीद है। आईएमएफ का अनुमान है कि वर्ष 2022 में यह 5.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 2.4 प्रतिशत रह जाएगी।

31 जनवरी, 2023 को पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वित्त वर्ष 2024 में भारतीय वास्तविक जीडीपी के 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान मोटे तौर पर विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों के बराबर है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि के लिए वास्तविक परिणाम संभवतः 6.0 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच होगा, जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक विकास के प्रक्षेपवक्र पर निर्भर करेगा। अधिक ऋण वितरण, पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ कॉर्पोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की बैलेंस शीट के मजबूत होने से विकास तेज होने की उम्मीद है। इसके अलावा आर्थिक विकास को अधिक समर्थन सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों के विस्तार और पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय रसद नीति और विनिर्माण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे पथ-प्रदर्शक उपायों से आएगा।

भले ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया, लेकिन वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान दिख रहा है। वैश्विक पण्य कीमतों में नरमी से पिछले कुछ

सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों के विस्तार और पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय रसद नीति और विनिर्माण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे पथ-प्रदर्शक उपायों से आएगा।

भले ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया, लेकिन वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान दिख रहा है। वैश्विक पण्य कीमतों में नरमी से पिछले कुछ महीनों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में कमी आई है। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2022 में घटकर 24 महीने के निचले स्तर 4.74 प्रतिशत पर आ गई।6 प्रतिशत की सीमा के दोनों ओर हेडलाइन मुद्रास्फीति की सीमित अस्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था के नीचे की ओर चल रहे समायोजन को दर्शाती है। तदनुसार, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2023 की बैठक में नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की मामूली वृद्धि की है, जबकि सख्ती चक्र के दौरान पहले उच्च वृद्धि हुई थी।

वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद घरेलू आर्थिक गतिविधि मजबूत बनी हुई है, जैसा कि जनवरी 2023 में 1.6 लाख करोड़ रुपये के दूसरे सबसे अधिक जीएसटी संग्रह में स्पष्ट है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में वृद्धि, लगातार बढ़ती वाणिज्यिक गतिविधि को दर्शाती है, ई-वे बिल उत्पादन की मात्रा में निरंतर वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में खर्च और मूल्य संवर्धन में वृद्धि की ओर इशारा करती है।

पीएमआई विनिर्माण द्वारा संकेतित विनिर्माण गतिविधि, जनवरी 2023 में विस्तारवादी क्षेत्र में मजबूती से बनी रही। पीएमआई विनिर्माण गतिविधि के प्रमाणों की पुष्टि करते हुए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और आठ मुख्य उद्योगों के सूचकांक (आईसीआई) ने भी दिसंबर 2022 में अच्छी वृद्धि प्रदर्शित की है, जिसमें अप्रैल-दिसंबर 2022 की अवधि में क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है।

सेवा क्षेत्र भी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर रहा है और उसे आगे बढ़ा रहा है। जनवरी 2023 तक, पीएमआई सेवाएं लगातार 18 महीनों तक विस्तारवादी क्षेत्र में बनी हुई हैं। गतिविधि में वृद्धि को अनुकूल मांग की स्थिति और नए काम में चल रही वृद्धि से समर्थन मिला है। वित्त वर्ष 2023-23 की अप्रैल-जनवरी अवधि (हवाई यात्री यातायात के मामले में अप्रैल-दिसंबर) के दौरान रेल, माल ढुलाई और हवाई साधनों में परिवहन सेवा गतिविधि पिछले दो वर्षों के इसी स्तर से काफी ऊपर रही।

कुल मिलाकर मांग की स्थिति अर्थव्यवस्था में निर्मित गति को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रही। जनवरी 2023 में ईंधन की मांग, जैसा कि ईंधन की खपत से पता चलता है, वित्त वर्ष 2023 में दूसरी सबसे अधिक थी। ऑटोमोबाइल की बिक्री और यूपीआई लेनदेन मूल्य और वॉल्यूम में लगातार वृद्धि भी स्वस्थ मांग की स्थिति को दर्शाती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण वितरण भी दोहरे अंकों के क्षेत्र में रहा। आरबीआई के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि

वर्तमान अवधि के साथ-साथ आने वाले वर्ष के लिए उपभोक्ता विश्वास में और सुधार हुआ है।

उपरोक्त घटनाक्रमों के संदर्भ में, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2023 को घोषित केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2024 के माध्यम से परिकल्पित भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़े हुए लचीलेपन पर भी संक्षेप में बात करना चाहूंगा।

- भारत का केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2024 जीडीपी के 6 प्रतिशत से कम के राजकोषीय घाटे का बजट बनाकर व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च विकास का समर्थन करने और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए कतिपय प्रयासों की भी घोषणा की गई है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित उपायों जैसे एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को राहत और कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी योजना से धन की लागत को कम करने और छोटे उद्यमों के क्षेत्र को मदद मिलने की उम्मीद है।
- वित्त वर्ष 2024 के बजट ने एक बार फिर केंद्र के पूंजीगत व्यय बजट को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।
- इसके अलावा, नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था (एनपीआईटीआर) के तहत मूल छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने और कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने से खर्च बढ़ने और खपत मांग बढ़ने की उम्मीद है।

2. **महत्वपूर्ण घटनाक्रम:**

(i) **भारत की जी 20 अध्यक्षता** के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख बैठकें और लेन-देन किए गए:

(क) इस माह के दौरान जी 20 इंडिया की अध्यक्षता के तहत निम्नलिखित वित्त ट्रैक बैठकें आयोजित की गईं:

- वित्तीय समावेशन के लिए पहली जी 20 वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई) कार्य समूह की बैठक 9-11 जनवरी, 2023 के दौरान कोलकाता में आयोजित की गई थी।
- जी-20 अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की पहली बैठक 16-17 जनवरी, 2023 के दौरान पुणे में आयोजित की गई थी। इस बैठक के मौके पर, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा 16 जनवरी, 2023 को "फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमॉरो" शीर्षक पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- पहली जी 20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह (आईएफए डब्ल्यूजी) की बैठक 30-31 जनवरी, 2023 के दौरान चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी।

(ख) व्यापार और निवेश, जी 20 और पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माननीय वित्त मंत्री और यूके के राजकोष के चांसलर के बीच एक टेली-वार्तालाप किया गया था।

(ग) भारत की जी-20 अध्यक्षता, क्षेत्र में आर्थिक विकास और श्रीलंका की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए अधोहस्ताक्षरी और उप प्रबंध निदेशक (आईएमएफ) के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ii) जनवरी 2023 में निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गईं:

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का.

(ख) गिफ्ट आईएफएससी में बीमा गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख विनियम अधिसूचित किए गए हैं:

- आईएफएससीए (नियुक्त एक्चुअरी) विनियम, 2022।
- आईएफएससीए (बीमा रिकॉर्ड का रखरखाव और जांच और निरीक्षण के लिए अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करना) विनियम, 2022।
- आईएफएससीए (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) विनियम, 2022।
- आईएफएससीए (बीमा उत्पाद और मूल्य निर्धारण) विनियम, 2022

(iii) भारत ने श्रीलंका के संभावित विस्तारित कोष सुविधा-समर्थित कार्यक्रम के लिए आईएमएफ को अपने वित्तपोषण आश्वासन से अवगत कराया और आईएमएफ समर्थित कार्यक्रम के तहत श्रीलंका की सार्वजनिक ऋण स्थिरता को बहाल करने के अनुरूप वित्तपोषण / ऋण राहत के साथ श्रीलंका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(iv) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित ऋण / अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

(क) विश्व बैंक के साथ निम्नलिखित ऋणों पर हस्ताक्षर किए गए थे:

- रेल लॉजिस्टिक्स परियोजना के लिए 245 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण।
- पंजाब में राजकोषीय और संस्थागत लचीलापन कार्यक्रम के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण।

(ख) एआईआईबी के निदेशक मंडल ने 'चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड सेक्शन II और III परियोजना' के लिए 378 मिलियन अमरीकी डालर के प्रस्तावित सॉवरेन समर्थित ऋण को मंजूरी दे दी।

(v) इस माह के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- आईएसबी, हैदराबाद में बेहतर परियोजना नियोजन, निष्पादन और निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधन उपकरण और कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- आईआईएम इंदौर में राजकोषीय नीति और लेखा और वित्त विश्लेषिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- **एनआईटीआईई मुंबई में परियोजना खरीद और जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।**

(vi) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित की गईं/में भाग लिया गया:

(क) भारत-कोरिया बीआईटी विवाद की अंतिम सुनवाई सिंगापुर न्यायाधिकरण में हुई।

(ख) आईएसडीएस सुधारों पर यूएनसीआईटीआरएएल कार्य समूह **III** का **44** वां सत्र वियना में आयोजित किया गया।

(ग) स्क्रीनिंग कमेटी जो बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तपोषण की मांग करने वाले प्रस्तावों पर विचार करती है।

(घ) विश्व बैंक समूह के वीपी और सीआरओ के साथ विश्व बैंक की पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क चर्चा।

(ङ) महामारी निधि बोर्ड की चौथी बैठक।

(च) भारत और रूस के बीच बीआईटी वार्ता का 10वां दौर।

(छ) भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बीआईटी वार्ता का 13वां दौर।

3. **न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन**

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. **एसीसी के निर्देशों/आदेशों का पालन न करना:** शून्य

5. **माह के दौरान मंजूर किए गए एफडीआई प्रस्तावों का ब्यौरा और विभाग में अनुमोदन हेतु प्रतीक्षाधीन एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:**

मंजूर किए गए प्रस्तावों की संख्या	:	02
विभाग में अनुमोदन हेतु प्रतीक्षारत	:	05